

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष— एम० के० सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 629—तीन / 2010 विरुद्ध आदेश, दिनांक 30—7—2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल सभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 156 / 07—08 अपील

लच्छीराम पुत्र शंकर आदिवासी उम्र 64 साल
निवासी ग्राम राडेप, परगना व जिला श्योपुर
मध्य प्रदेश

आवेदक

विरुद्ध

- 1 रामस्वरूप पुत्र मांगीलाल आदिवासी
उम्र 46 साल, निवासी ग्राम नयागांव,
तहसील व जिला श्योपुर म० प्र०
- 2 चेत्या पुत्र सूरजा आदिवासी
- 3 अंशु पुत्र सूरजा आदिवासी
निवासीगण ग्राम राडेप हाल निवासीगण
ग्राम आवादा, तहसील व जिला श्योपुर म० प्र०

—अनावेदकगण

श्री एस० के० अवरथी अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6-12-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल सभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 156 / 07—08 अपील में पारित आदेश दिनांक 30—7—2009 के विरुद्ध म० प्र० भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है।

(M)

P.M.

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील श्योपुर के ग्राम रापेड़ में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक ३११ रकबा ५ बीघा ५ बिस्वा जिसकी अभिलिखित भूमिस्वामिनी मृतक केशरबाई बेवा हीरा सहर थी। अभिलिखित भूमि-स्वामिनी केशरबाई की मृत्यु हो जाने के कारण अनावेदक क्रमांक १ रामस्वरूप पुत्र मांगीलाल द्वारा विवादित भूमि पर मृतक केशरबाई के स्थान पर वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने बाबत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अनावेदक क्रमांक २ एवं ३ द्वारा वारिसान के आधार पर अपने नाम नामांतरण किये जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया। नामांतरण विवादित होने के कारण पटवारी मौजा द्वारा प्रकरण निराकरण के लिये विचारण न्यायालय को भेजा। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक १५/०५-०६/अ-६ पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक २९-६-२००७ से अनावेदक क्रमांक १ रामस्वरूप द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा को प्रमाणित न मानकर वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण कराये जाने बाबत प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त करते हुये आवेदक लच्छीराम के नाम नामांतरण स्वीकार किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक २९-६-०७ से परिवेदित होकर अनावेदक क्रमांक १ रामस्वरूप द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक ७०/०६-०७/अपीलमाल पर दर्ज की जाकर पारित विचाराधीन आदेश दिनांक २८-२-२००८ से स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक २९-६-२००७ निरस्त करते हुये प्रकरण विचारण न्यायालय को उभयपक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में विधिवत आदेश पारित किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक २८-२-२००८ से दुखी होकर आवेदक द्वारा अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक ३०-७-२००९ द्वारा अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

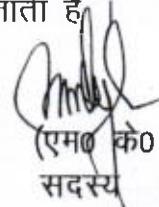
3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किए गए हैं।

JK

JK

- 4/ अनावेदक कमांक 1 की ओर से विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।
- 5/ अनावेदक कमांक 2 एवं 3 एकपक्षीय हैं।
- 6/ उभयपक्षों के विद्वान् अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्रकरण वसीयत के आधार पर नामांतरण का है। प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर नामांतरण किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने यह पाया है कि विचारण न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर संहिता की धारा 109 एवं 110 के तहत नामांतरण किए जाने के संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई है और उक्त कारण से उन्होंने विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त कर पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय ने की है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपीलीय न्यायालयों के आदेशों में कोई विधिक या सारबान त्रुटि नहीं हैं और उनके आदेश अभिलेख पर आधारित हैं, जिनमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश रिथर रखा जाता है।



(एम० को० सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
गवालियर

